

तब्बती शरणाधियों के पुनर्वास के लिए लद्दाख में आवंटित भूमि

2513. श्री कुशोक चाकुला : क्या भूमि और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणाधियों के पुनर्वास के लिये प्रारम्भ में लद्दाख में 1200 एकड़ कृषि योग्य भूमि आवंटित करने की योजना बनाई थी किन्तु उसमें से अभी तक केवल 600 एकड़ भूमि ही निर्धारित की गई है तथा इस भूमि का भी अधिकांश भाग अनुपजाऊ एवं निरर्थक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

भूमि और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० झाडिलकर) : (क) और (ख). अभिचैनमें-यांग नहर के क्षेत्र में आने वाली 1200 एकड़ भूमि, जो जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा लद्दाख में दी गई थी उस पर 305 तिब्बती शरणार्थी परिवारों को बसाने की एक योजना जून, 1971 में संजूर की गई थी। योजना को संजूर करने में पूर्व कृषि मंत्रालय के भूमि सर्वेक्षण दल द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था और दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर यह निश्चय किया गया कि लगभग 800 एकड़ भूमि कृषि के लिए, 55 एकड़ भूमि बागवानी और सब्जियां उगाने के लिये, 250 एकड़ भूमि जो कृषि के लिये अयोग्य थी, तिब्बती शरणार्थी ममुदाय के प्रयोग के लिये ईंधन और लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु कृषि लगाने के लिये तथा शेष भूमि भवनों, सड़कों आदि के लिये प्रयोग में लाई जायेगी। मूल योजना के आधार पर 600 एकड़ भूमि तिब्बती शरणाधियों को पहले ही आवंटित की जा चुकी है। भूमि के अनुपजाऊ एवं निरर्थक होने की आशंका ठीक नहीं है। राज्य सरकार के अनुसार भूमि कृषि योग्य है। कुछ परिस्थितियों के कारण

क्षेत्र में शेष भूमि आवंटन के लिये अब उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार अपेक्षित शेष भूमि किसी अन्य क्षेत्र में ढूँढ रही है।

तिब्बत में चीन के तरल ईंधन चालित बिलास्टिक मिजाइल्स का संभार

2514. श्री शिवकुमार शास्त्री :

श्री कमल विश्व मधुकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश समाचार पत्र 'जेन्स वेमन्स मिस्टैम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन ने 2,485 किलोमीटर तक आक्रमण की क्षमता रखने वाले तरल ईंधन चालित बिलास्टिक मिजाइल्स तिब्बत में एकत्र कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) चीन द्वारा तिब्बत में बिलास्टिक मिसाइल नियोजित करने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

Production of Steel in 1972-73

2515. SHRI P. M. MEHTA:

SHRI PURUSHOTTAM KAKODKAR:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether steel production in the current year would be higher in 1971-72;

(b) whether profits would be lower than in the previous year; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) It is expected that the aggregate production of steel from the main steel plants this year will be higher than in 1971-72.

(b) and (c) The working results of the concerned steel industry are likely to be better than in 1971-72.

Discovery of copper deposits in Bhalghat

2516. SHRI JAGANNATH MISHRA;
SHRI RANABAHADUR
SINGH:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey of India have located copper deposits in Bhalghat District in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) and (b). As a result of surface and subsurface investigations carried out by Geological Survey of India in recent years, reserves of about 40 million tonnes of copper ore with about 1.35 percent copper content have been estimated so far at Malanjkhanda in Bhalghat district, Madhya Pradesh. Further detailed exploration work is in progress.

Proposal for a Marketing Corporation for coal

2517. SHRI INDER J. MALHOTRA:
Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government are examining a proposal to set up a Marketing Corporation for coal;

(b) if so, at which stage the proposal has reached and outline of the marketing plan; and

(c) whether there is any proposal to re-introduce control on coal in the context of the above proposal or otherwise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) and (b). A Committee of officials has been set up to examine the problems regarding coal marketing in the public sector including the feasibility of setting up a central coal marketing corporation. The report of the Committee is awaited.

(c) One of the ways to rationalise the distribution of coal among consumers, particularly in the context of continuing shortage of the Railway wagons is to re-impose control on the distribution of coal. A proposal in this behalf is under consideration.

Long wait for issue of passports

2518 SHRI ARVIND NETAM Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that persons have to wait for a long time for the issue of Passports even after getting the attestation from Deputy Secretary/First Class Magistrate;

(b) whether Government have laid down certain time limit for the issue of the passports; and

(c) the number of passports issued during the last six months, which were attested by Deputy Secretary/First Class Magistrate and the minimum and the maximum time taken by the Regional Passport Office, New Delhi to issue the Passports?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and (b). Sir, the position is that there are standing instructions in this regard, enjoining upon the Regional Passport Officers to grant passports within 48 hours, to applicants who produce Verification Certificates issued by officers of the rank of Deputy Secretary/First Class Magistrate, and above. The R.P.Os, however, are required to ensure that the applications are